भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1717

08 दिसंबर, 2021

"चीनी निर्यात"

1717. श्री विद्युत बरन महतो:

श्री संजय सदाशिव राव मांडलिक:

श्री रवि किशन:

श्री रविन्द्र कुशवाहा:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री सुब्रत पाठक:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का चीनी निर्यात चालू वर्ष 2020-21 में 20 प्रतिशत बढ़कर 7.1 मिलयन टन हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2021-22 के दौरान घरेलू उपभोग के विरुद्ध अनुमानित चीनी उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार देश में अतिरिक्त चीनी भंडार निपटान करने/उपयोग करने के कई तरीको को आजमा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या देश में अधिकांश सहकारी चीनी मिलें घाटे में चल रही है;

(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं; और

(च) चीनी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): चीनी मौसम 2019-20 में 59.60 लाख टन चीनी के निर्यात की तुलना में चीनी मौसम 2020-21 में लगभग 70 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है जो 17.45% अधिक है।

(ख): वतर्मान चीनी मौसम 2021-22 में 270 लाख टन के अनुमानित घरेलू उपभोग के लिए 35 लाख टन चीनी इथेनॉल हेतु डाइवर्ट करने के बाद लगभग 308 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान है।

...2/-

(ग): चीनी मिलों के पास उपलब्ध अधिशेष चीनी के स्टॉक को समाप्त करने, ताकि चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार हो जिससे वे किसानों के गन्ना बकाया का समय पर भुगतान करने में समर्थ हों, के उद्देश्य से सरकार अधिशेष चीनी का निर्यात करने और अधिशेष गन्ना/चीनी इथेनॉल हेतु डाइवर्ट करने के लिए चीनी मिलों को प्रोत्साहित कर रही है। पिछले चीनी मौसम 2020-21 में लगभग 70 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया और लगभग 22 लाख टन चीनी को इथेनॉल के लिए डाइवर्ट किया गया।

(घ) और (ड.): किसी भी चीनी कारखाने (सहकारी/निजी/सार्वजनिक उपक्रम) की वित्तीय स्थिति संबंधी आंकड़ें खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग नहीं रखता है।

तथापि, देश में चीनी मिलों, जिनमें सहकारी चीनी मिलें भी शामिल हैं, की नकदी की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार समय-समय पर विभिन्न उपाय करती आ रही है जैसे, गन्ने की लागत की भरपाई करने के लिए चीनी मिलों को सहायता देना, चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारित करना, बफर स्टॉक के रख-रखाव के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देना, चीनी के निर्यात को सुगम बनाने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, चीनी मिलों को सरल ऋण प्रदान करना आदि।

इसके अलावा, चीनी की नकदी की स्थिति में सुधार करने और चीनी के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार अतिरिक्त गन्ना/चीनी को इथेनॉल, जिसे पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाता है, के लिए डाइवर्ट करने हेतु चीनी मिलों को प्रोत्साहित कर रही है। पिछले चार चीनी मौसमों 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में; तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को इथेनॉल की बिक्री से चीनी मिलों/डिस्टिलरियों द्वारा लगभग 35000 करोड़ रुपए का राजस्व सृजित हुआ है, जिससे किसानों के गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान में सहायता मिली है।

(च): चीनी के निर्यात को सुगम बनाने, जिससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार हो सके ताकि वे किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का निपटान करने में समर्थ हों, के लिए केंद्रीय सरकार ने चीनी मौसम 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में चीनी मिलों को सहायता प्रदान की है। चीनी के निर्यात को सुगम बनाने के लिए चीनी मौसम 2015-16 से विभिन्न चीनी मिलों को लगभग 12900 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसके परिणामस्वरूप, चीनी मौसम 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः लगभग 16.5 लाख टन, 6.2 लाख टन, 38 लाख टन, 59.60 लाख टन और 70 लाख टन का निर्यात किया गया। वैश्विक स्तर पर चीनी की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अब चीनी के मूल्य स्थिर हैं जिसके कारण वर्तमान में चीनी का निर्यात बिना सहायता के भी सुकर है; वर्तमान चीनी मौसम 2021-22 में लगभग 30 लाख टन की संविदाएं पहले ही हस्ताक्षरित हो चुकी हैं।

इसके अलावा, देश से अतिरिक्त चीनी के निर्यात को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा चीनी के निर्यात पर सीमा शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है।